



एग्री मैगज़ीन

(कृषि लेखों के लिए अंतरराष्ट्रीय ई-पत्रिका)

वर्ष: 02, अंक: 10 (अक्टूबर, 2025)

www.agrimagazine.in पर ऑनलाइन उपलब्ध

© एग्री मैगज़ीन, आई. एस. एस. एन.: 3048-8656

पशुपालन: लघु एवं सीमांत कृषकों की आर्थिक जीवनरेखा

*डॉ. स्वप्नील समाधान वानखडे¹ एवं डॉ. शुभांगी संभाजी व्यवहारे²

¹सहायक प्राध्यापक, पशुविकृतीशास्त्र विभाग, अपोलो कॉलेज ऑफ़ वेटेरिनरी मेडिसिन, जयपूर-राजूवास, भारत

²पशुधन विकास अधिकारी, पशुवैधकीय दवाखाना श्रेणी -१ निब्रळ, ता. अकोले जि. अहिल्यानगर, महाराष्ट्र, भारत

*संवादी लेखक का ईमेल पता: swapnil.wankhade95@gmail.com

भारत की लगभग 65-70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, और इन ग्रामीण परिवारों में से अधिकांश की आजीविका कृषि और उससे संबद्ध व्यवसायों पर निर्भर है। इनमें से लगभग 86 प्रतिशत किसान लघु (Small) एवं सीमांत (Marginal) श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जिनकी जोत का आकार 2 हेक्टेयर से भी कम है। ऐसे किसानों के लिए केवल फसल उत्पादन पर निर्भर रहना आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त नहीं होता। इसीलिए पशुपालन (Animal Husbandry) एक प्रमुख वैकल्पिक एवं पूरक व्यवसाय के रूप में उभरता है, जो न केवल आय के विविध स्रोत प्रदान करता है, बल्कि सामाजिक, पोषणीय तथा आर्थिक स्थिरता में भी योगदान देता है।

गरीबी केवल आर्थिक अभाव नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता और मानव अधिकारों के उल्लंघन का प्रतीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन का प्रभावी माध्यम पशुपालन है, क्योंकि यह लघु एवं सीमांत किसानों को नियमित आय, रोजगार और पोषण सुरक्षा प्रदान करता है। इसी उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 17 अक्टूबर को “अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस” घोषित किया, ताकि ऐसे सतत आजीविका साधनों—जैसे पशुपालन—के माध्यम से विश्व स्तर पर गरीबी समाप्त करने के प्रयासों को प्रोत्साहन मिल सके।

पशुपालन का स्वरूप और दायरा

पशुपालन केवल दूध उत्पादन तक सीमित नहीं है। इसमें अनेक गतिविधियाँ सम्मिलित हैं —

- दुग्ध उत्पादन (Dairy farming)
- कुक्कुट पालन (Poultry farming)
- मधुमक्खी पालन (Apiculture)
- बकरी पालन (Goat farming)
- भेड़ पालन एवं ऊन उत्पादन (Sheep rearing & wool production)
- सूअर पालन (Pig farming)
- मत्स्य पालन (Aquaculture)

इन गतिविधियों से ग्रामीण कृषकों को नियमित नकद आय, पोषण, तथा रोजगार प्राप्त होता है।

लघु एवं सीमांत कृषकों की आर्थिक स्थिति

लघु एवं सीमांत कृषकों की सबसे बड़ी समस्या उनकी जोखिम वहन क्षमता का निम्न स्तर है।

- सीमित भूमि के कारण वे बड़े पैमाने पर फसल उत्पादन नहीं कर सकते।
- जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ आदि प्राकृतिक विपदाएँ उनकी आजीविका को अत्यधिक प्रभावित करती हैं।
- नकदी प्रवाह (cash flow) की कमी के कारण वे आधुनिक कृषि तकनीकों में निवेश नहीं कर पाते।

ऐसी परिस्थिति में पशुपालन एक जोखिम-संतुलनकारी (risk-mitigating) और आय-विविधीकरण (income diversification) का माध्यम बनता है।

पशुपालन के आर्थिक लाभ

- नियमित और स्थायी आय स्रोत - कृषि की तुलना में पशुपालन से आय वर्षभर मिलती है — दूध, अंडे, मांस, गोबर एवं अन्य उत्पादों की बिक्री से रोजमर्रा की नकद आमदनी होती है।

- जोखिम प्रबंधन और लचीलापन - फसल विफलता या बाजार मूल्य में गिरावट की स्थिति में, पशुपालन किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। इसे “सजीव बैंक (Living Bank)” कहा जाता है क्योंकि पशुओं को आवश्यकता पड़ने पर नकद में परिवर्तित किया जा सकता है।
- खाद्य एवं पोषण सुरक्षा - दुग्ध, अंडा, मांस आदि उच्च जैविक मूल्य वाले प्रोटीन के स्रोत हैं। ग्रामीण परिवारों में कुपोषण की समस्या को दूर करने में पशुपालन सहायक है।
- रोजगार सृजन - पशुपालन श्रम-सघन (labour intensive) क्षेत्र है। इसमें परिवार के सभी सदस्य, विशेषकर महिलाएँ, योगदान देती हैं। भारत में ग्रामीण महिलाओं का लगभग 70-75% योगदान पशुधन प्रबंधन में होता है।

सामाजिक और लैंगिक (Gender) प्रभाव

पशुपालन ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम है।

- महिलाएँ दुग्ध उत्पादन, पशु आहार तैयार करने, दुधारू पशुओं की देखभाल, सफाई आदि कार्यों में अग्रणी भूमिका निभाती हैं।
- सहकारी दुग्ध समितियों (जैसे अमूल, सुदामिनी, पाराग, वारणा) में महिला सदस्यों की भागीदारी से उनकी निर्णय लेने की क्षमता और आत्मनिर्भरता बढ़ी है।
- इससे सामाजिक समानता एवं पारिवारिक समृद्धि को बल मिला है।

सतत कृषि और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान

पशुपालन और कृषि का एकीकृत मॉडल (Integrated Farming System) प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं पर्यावरणीय संतुलन हेतु अत्यंत प्रभावी है।

- गोबर एवं मूत्र का उपयोग जैविक खाद एवं जैविक कीटनाशक के रूप में किया जाता है।
- फसल अवशेष पशु चारे के रूप में उपयोग होते हैं।
- इस प्रकार पोषक चक्र (nutrient cycle) बंद होता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटती है।

प्रमुख चुनौतियाँ

हालाँकि पशुपालन की अपार संभावनाएँ हैं, लेकिन अनेक बाधाएँ भी विद्यमान हैं—

1. उच्च नस्लीय पशुओं की कमी और सीमित कृत्रिम गर्भाधान सुविधाएँ।
2. पशुचिकित्सा सेवाओं एवं रोग नियंत्रण उपायों की अपर्याप्त उपलब्धता।
3. संतुलित आहार (Balanced feed) की कमी और बढ़ती लागत।
4. बाजार तक पहुँच (Market linkage) की समस्या, विशेषकर दुग्ध उत्पादों के लिए।
5. वित्तीय सहायता एवं बीमा योजनाओं का अभाव या जटिल प्रक्रिया।

सरकारी योजनाएँ और नीतिगत पहलें

भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने पशुपालन क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं —

- राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission – NLM): पशु चारा, नस्ल सुधार, एवं क्षमता निर्माण पर केंद्रित योजना।
- राष्ट्रीय गोकुल मिशन (Rashtriya Gokul Mission): देशी नस्लों के संरक्षण, संवर्द्धन और आनुवंशिक सुधार हेतु।
- डेयरी उद्यमिता विकास योजना (Dairy Entrepreneurship Development Scheme – DEDS): युवा उद्यमियों को डेयरी इकाइयाँ स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- एनिमल हसबैंड्री इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (AHIDF): पशुपालन अवसंरचना निर्माण, प्रसंस्करण एवं वैल्यू चेन विकास के लिए।
- राष्ट्रीय डेयरी योजना (National Dairy Plan – NDP): दूध उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए लागू।

सहकारी आंदोलन का योगदान (Cooperative Model)

भारत का अमूल मॉडल पशुपालन क्षेत्र के लिए आदर्श उदाहरण है।

- अमूल (Anand Milk Union Limited) ने 3.6 मिलियन से अधिक दुग्ध उत्पादकों को संगठित किया।
- इस मॉडल ने ग्रामीण किसानों को न्यायसंगत मूल्य, प्रशिक्षण, और तकनीकी सहायता प्रदान की।
- इस प्रकार सहकारी ढाँचे ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया जीवन दिया।

भविष्य की संभावनाएँ

भारत में पशुपालन क्षेत्र की वृद्धि दर 6-8% प्रतिवर्ष है, जो कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि दर (3-4%) से अधिक है। भविष्य में निम्नलिखित पहलुओं पर ध्यान देकर इसे और सशक्त बनाया जा सकता है:

- आधुनिक तकनीक जैसे कृत्रिम गर्भाधान, जीनोमिक चयन (Genomic Selection) एवं स्मार्ट फीडिंग सिस्टम का प्रयोग।
- डिजिटल पशु स्वास्थ्य निगरानी (Digital Livestock Health Monitoring) और ई-डेयरी प्लेटफॉर्म।
- बायोगैस संयंत्र, गोबरधन योजना, एवं कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहन।



निष्कर्ष

पशुपालन भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जीवंत आधार है। यह केवल कृषि का पूरक क्षेत्र नहीं, बल्कि लघु एवं सीमांत कृषकों की आर्थिक स्थिरता, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक विकास का स्तंभ है। यदि नीति निर्धारक, वैज्ञानिक संस्थाएँ, सहकारी समितियाँ, और किसान समुदाय मिलकर इस क्षेत्र के विकास में निवेश करें, तो पशुपालन न केवल ग्रामीण गरीबी उन्मूलन का साधन बनेगा, बल्कि भारत को वैश्विक पशुधन उत्पादक देश के रूप में सशक्त करेगा।

संदर्भ

- भारत सरकार, पशुपालन एवं डेयरी विभाग – वार्षिक रिपोर्ट (2023-24)
- 20वीं पशुधन गणना, भारत (2019)
- एफएओ - पशुधन और आजीविका रिपोर्ट, 2022
- योजना आयोग (नीति आयोग), "ग्रामीण आजीविका और पशुपालन", 2021
- एनडीडीबी (राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड) सांख्यिकीय बुलेटिन, 2023
- नाबार्ड - डेयरी उद्यमिता योजनाओं पर वार्षिक रिपोर्ट, 2022
- पशुधन जनगणना और कृषि सांख्यिकी पर एक नज़र, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।